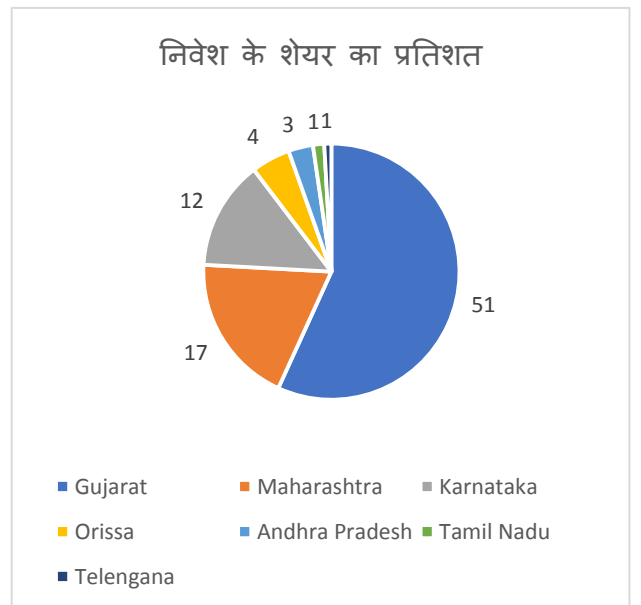
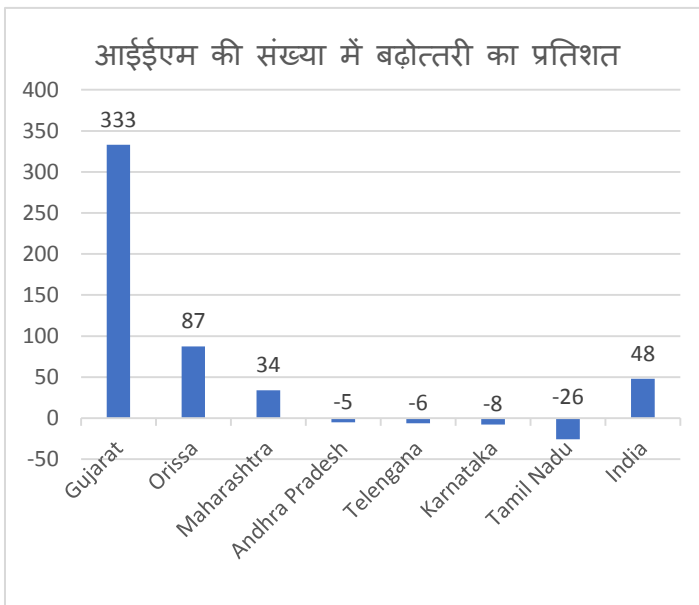


औद्योगिक नीति 2020: आत्मनिर्भर गुजरात के लिए गुजरात के उद्योग का विकास

अगस्त 7, 2020

- गुजरात औद्योगिक नीति 2015, 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो गई है। इसे नई नीति के जारी होने की तारीख या 31 दिसंबर 2020 में से जो भी पहले हो, तक आगे बढ़ा दिया गया।
- गुजरात औद्योगिक नीति 2015 समाप्त हो गई है और इसने पूरे राज्य की औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- इस नीति की सफलता का मूल्यांकन निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है:
 1. गुजरात फाइल किए गए आईईएम (औद्योगिक उद्यमिता जापन) की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है और डीपीआईआईटी, भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में वास्तविक निवेश की रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें भारत में आईईएम के ~51% शेयर फाइल किए गए और 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्रस्तावित है।
 2. जबकि भारत में 2019 में प्रस्तावित निवेश (आईईएम) में 48% की वृद्धि हुई वहीं गुजरात में पिछले वर्ष की तुलना में 333% की वृद्धि दर्ज की गई।



निवेश विविध क्षेत्रों में भी हुए हैं जिनमें कपड़ा, रसायन, ऑटो और ऑटो के पुर्जे, प्लास्टिक, ऊर्जा और बिजली, खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं

| क्षेत्र | कंपनियां |
|---------------------------|---|
| ऑटो के पुर्जे का निर्माण | <ul style="list-style-type: none"> सम जेडएफ कॉन्पोनेंट्स प्रा. लि. (सोमिक इशिकावा इंका, जापान और जेडएफ फ्रेडरिकशाफेन एजी, जर्मनी के बीच संयुक्त उपक्रम) मदरसन सुमी सिस्टम्स लि. |
| इंजेक्शन मोल्डिंग निर्माण | <ul style="list-style-type: none"> सेकिसुई डिलिम मोल्डिंग प्रा. लि. (मेसर्स सेकिसुई केमिकल लि., जापान और मेसर्स दीप्ति लाल जज माल प्रा. लि., भारत के बीच संयुक्त उपक्रम) |
| तार एवं केबल निर्माण | <ul style="list-style-type: none"> पॉलीकैब इंडिया लि. |
| पवन टरबाइन ब्लेड निर्माण | <ul style="list-style-type: none"> सेनवियॉन विंड टेक्नोलॉजी प्रा. लि. |
| अभियांत्रिकी | <ul style="list-style-type: none"> मैक्वेल ऑटो इंजीनियरिंग प्रा. लि. |
| नवीकरणीय ऊर्जा | <ul style="list-style-type: none"> एबेलॉन को जेन लिमिटेड |
| रसायन | <ul style="list-style-type: none"> डीडी केमिकल्स प्रा. लि. ग्रेनुला मास्टरबैचेज इंडियन प्रा. लि. फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि. |
| वस्त्र | <ul style="list-style-type: none"> स्वैन मेडिकॉट एलएलपी क्रिएटिव गारमेंट्स प्रा. लि. कामदगिरि फैशन लिमिटेड |
| कागज के उत्पाद | <ul style="list-style-type: none"> लेट्रा ग्राफिक्स प्रा. लि. |
| धातुकर्म उद्योग | <ul style="list-style-type: none"> डॉम्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. |
| दवा | <ul style="list-style-type: none"> एक्युलाइफ हेल्थकेयर प्रा. लि. |

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में; भारत में एफडीआई में 14% की वृद्धि हुई जबकि गुजरात में पिछले वर्ष की तुलना में एफडीआई प्रवाह में 240% की अधिकतम राष्ट्रीय वृद्धि दर्ज की।
- गुजरात में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में बेरोजगारी की सबसे कम दर 3.4% गुजरात में है।

| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | शहरी आबादी का बेरोजगारी प्रतिशत |
|---------------------------|---------------------------------|
| गुजरात | 3.4 |
| कर्नाटक | 5.3 |
| महाराष्ट्र | 6.6 |
| तमिलनाडु | 7.2 |
| आंध्र प्रदेश | 7.8 |
| हरियाणा | 9 |
| केरल | 11 |
| तेलंगाना | 11.5 |
| संपूर्ण भारत | 8 |

5. गुजरात में एमएसएमई की संख्या में वर्ष 2014-2015 से 60% की वृद्धि हुई और अभी गुजरात में एमएसएमई, जो रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है और बड़े औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, की संख्या 3.5 मिलियन से अधिक है।

➤ यदि आप राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालते हैं,

1. गुजरात भारत के उत्पादन के ~ 17% के साथ औद्योगिक उत्पादन के मामले में देश में पहले स्थान पर है

2. डीपीआईआईटी, भारत सरकार द्वारा जारी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग, 2018 में राज्य की पहचान सर्वश्रेष्ठ निर्वाहक राज्य के रूप में की गई है

3. वर्ष 2019 में वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स और लीड्स इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा

➤ गुजरात में पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात लगातार दोहरे अंक की विकास दर हासिल कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में, राज्य ने सतत मूल्य पर 10.14% की औसत वृद्धि दर दर्ज की।

➤ यदि हम सब्सिडी राशि की बात करते हैं, तो पिछले पांच वर्षों में इसमें गुणात्मक वृद्धि की दर से लगभग 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

➤ इसी तरह के विकास के पैटर्न को देखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि नई गुजरात औद्योगिक नीति 2020 के लिए औसत वार्षिक परिव्यय ₹ 8,000 करोड़ होगा

➤ इस गति को और मजबूत करने और वर्तमान विकास दर को बढ़ाने के लिए नई गुजरात औद्योगिक नीति 2020 बनाई गई है। सहायक रोजगार, सभी क्षेत्रों में मूल्यवर्धन, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, उद्योग 4.0 विनिर्माण के साथ उत्पादकता में वृद्धि, नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र और अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयास किए गए हैं ताकि राज्य को “आत्मनिर्भर गुजरात” की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। यह एक आधुनिक गुजरात को आकार देने में सक्षम होगा जो एक आधुनिक भारत के सपने को पूरा करता है।

➤ हमने हर क्षेत्रों में अधिक संतुलित विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

- गुजरात की ताकत अपने मजबूत और विविध हितधारकों, अर्थात् उद्योग, औद्योगिक संघों, मंडलों और शिक्षाविदों के साथ निरंतर बातचीत में है।
- हमने 9 टास्क फोर्स समितियों का गठन किया था, जिन्होंने गंभीर और उत्पादक बैठकों के कई दौर आयोजित किए, जिससे हमें नई गुजरात औद्योगिक नीति 2020 के लिए रचनात्मक सुझाव मिले।
- इस नीति में वैश्विक और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रवृत्तियों और क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उद्योग द्वारा इंगित अधिकांश सुझावों को शामिल किया गया है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन, अगली पीढ़ी के उद्योग 4.0 के नेतृत्व में विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित "आत्मनिर्भर भारत" की परिकल्पना में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके।

- जैसा कि आंकड़े खुद बोलते हैं, हमारे जीवंत राज्य में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और इसीलिए गुजरात औद्योगिक नीति 2015 की कई सुविधाओं को जारी रखा गया है। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

1. ध्यान देने योग्य क्षेत्र:

वैश्विक निवेश रुझानों के आधार पर ध्यान देने योग्य 15 क्षेत्रों की परिकल्पना की गई है, एकीकृत मूल्य श्रृंखला, निर्यात, भारत सरकार द्वारा नीतियां, नीति आयोग आदि को मजबूत करने की आवश्यकता। ध्यान देने योग्य क्षेत्रों को दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य क्षेत्र और सनराइज क्षेत्र। मुख्य क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जहां गुजरात में पहले से ही एक मजबूत विनिर्माण आधार है और वैश्विक स्तर पर इसे और तेज किए जाने की क्षमता है। सनराइज क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें तकनीकी उन्नति की महत्वपूर्ण क्षमता है और यह सतत आर्थिक विकास में योगदान कर सकते हैं। इस नीति के तहत ध्यान देने योग्य क्षेत्रों को इसके हिस्से के रूप में वृद्धिशील प्रोत्साहन दिया जाएगा।

| | |
|----------------------|---|
| मुख्य क्षेत्र | <ol style="list-style-type: none"> 1. विद्युत मशीनरी एवं उपकरण 2. औद्योगिक मशीनरी एवं उपकरण 3. ऑटो एवं ऑटो के पुर्जे 4. सेरामिक्स 5. तकनीकी टेक्स्टाइल्स 6. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण |
|----------------------|---|

| | |
|-----------------------|--|
| | 7. दवा एवं चिकित्सीय उपकरण 8. रत्न एवं आभूषण 9. रसायन (नामित क्षेत्र में) |
| सनराइज क्षेत्र | 1. उद्योग 4.0 विनिर्माण 2. विद्युत वाहन एवं इसके पुर्जे 3. कचरा प्रबंधन योजनाएं 4. हरित ऊर्जा (सोलर एवं वायु उपकरण) 5. पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक सामग्री (पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प) 6. किसी भी क्षेत्र की 100% निर्यात उन्मुख इकाइयां |

2. पूंजीगत सब्सिडी:

जीएसटी लागू होने के बाद से, कंपनियों को राज्य के अंदर बेचे जाने वाले सामान पर "शुद्ध एसजीएसटी" के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा था। राज्य के अंदर खपत होने वाले माल के कर की गणना में कई जटिलताएं थीं। इसलिए, एसजीएसटी से प्रोत्साहन हटाने का साहसिक निर्णय लेने वाला गुजरात पहला राज्य है। पूंजीगत सब्सिडी के रूप में राज्य में विनिर्माण परिचालन स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगों को निर्धारित पूंजी निवेश का 12% तक दिया जाएगा। इसलिए, प्रोत्साहन राशि अब अधिक अनुमानित और पारदर्शी होगी और इस प्रकार उद्योग को तेजी से निर्णय लेने में मदद करेगी।

किसी विशेष इकाई को दिए जाने वाले प्रोत्साहन की राशि पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इससे राज्य में बड़े निवेश को आधार बनाने में मदद मिलेगी।

| तालुका कैटेगरी | सामान्य क्षेत्र | ध्यान देने योग्य क्षेत्र (15) |
|----------------|-----------------|-------------------------------|
| कैटेगरी 1 | • एफसीआई का 10% | • एफसीआई का 12% |
| कैटेगरी 2 | • एफसीआई का 8% | • एफसीआई का 10% |
| कैटेगरी 3 | • एफसीआई का 4% | • एफसीआई का 6% |

- यह लाभ 40 करोड़ की वार्षिक सीमा के अधीन 10 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा।
- यदि निर्धारित नकद सब्सिडी 40 करोड़ प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के कारण 10 साल की अवधि के भीतर वितरित नहीं की जा सकी तो ऐसी इकाई के लिए 10 वर्ष

की निर्धारित अवधि को 40 करोड़ की वार्षिक सीमा की शर्त के साथ अतिरिक्त 10 वर्षों तक बढ़ा दिया जाएगा।

- यदि निर्धारित नकद सब्सिडी 40 करोड़ प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के कारण 10 साल की अवधि के भीतर वितरित नहीं की जा सकी तो बिना किसी अधिकतम सीमा के 20 वर्ष की समान किस्तों में कुल नकद सब्सिडी का वितरण कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, नए उद्योगों को 5 साल के लिए बिजली शुल्क से छूट मिलती रहेगी।

इसके साथ, गुजरात अन्य राज्यों की तुलना में उद्योगों को काफी ज्यादा प्रोत्साहन देगा।

3. एमएसएमई:

एमएसएमई की परिभाषा भारत सरकार की परिभाषा के अनुरूप होगी, ताकि बड़ी संख्या में इकाइयां एमएसएमई नीतियों के तहत प्रावधानों का लाभ उठा सकें।

यह नीति एमएसएमई को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से एमएसएमई को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सरकार वैश्विक स्तर पर स्वीकृत प्रमाणपत्रों को अपनाकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके उत्पादों की मार्केटिंग करके प्रौद्योगिकियों के उन्नयन में एमएसएमई की सहायता करेगी।

3.1 पूंजीगत सब्सिडी: एमएसएमई योग्य ऋण राशि के 25% तक की पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र होंगे, जो 35 लाख तक की होगी। इसके अतिरिक्त, यदि निर्धारित पूंजी निवेश 10 करोड़ से ज्यादा है तो इकाई 10 लाख तक की अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र होगी।

3.2 ब्याज सब्सिडी: एमएसएमई 7 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रति वर्ष 35 लाख रुपये तक के सावधि ऋण पर लगाए गए ब्याज के 7% तक ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।

एससी / एसटी उद्यमी / शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमी / महिला उद्यमी / विनिर्माण क्षेत्र के स्टार्ट अप को 1% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा।

इसके अलावा, ऋण स्वीकृति की तिथि पर 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमी को 1% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाएगी

3.3 सेवा क्षेत्र के एमएसएमई: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। कई सेवाएं अन्य प्राथमिक और माध्यमिक उद्योगों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं। नई गुजरात औद्योगिक नीति, 2020 सालाना 7% तक की ब्याज सब्सिडी की पेशकश करेगी, जो राज्य में इन सेवा क्षेत्र के एमएसएमई के वित्तीय सेवा, चिकित्सीय सेवा, ऑडियो विजुअल सेवा, निर्माण से संबंधित इंजीनियरिंग और पर्यावरण सेवाओं आदि से जुड़े लोगों के लिए होगी।

इसके साथ ही, राज्य बड़े उद्यमों के लिए सेवा क्षेत्र नीति पर काम कर रहा है।

3.4 एमएसएमई द्वारा विदेशी प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण: सरकार पहली बार विदेशी पेटेंट प्राप्त प्रौद्योगिकियों की लागत का 65% तक की सहायता प्रदान करेगी (अधिकतम सहायता 50 लाख तक)। यह हमारे एमएसएमई के विनिर्माण कौशल को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा।

3.5 एमएसएमई को बाजार विकास सहायता: एमएसएमई को अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में प्रोत्साहित करने के लिए, नई औद्योगिक नीति भारत में प्रदर्शन के लिए स्टॉल के किराए का 75% या 2 लाख तक और भारत के बाहर प्रदर्शन के लिए स्टॉल के किराए का 60% या 5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

3.6 सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहन: एमएसएमई में छत सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के उद्देश्य से, इकाइयों की खपत की गणना के लिए बिजली चक्र 15 मिनट से सुबह 7 बजे - शाम 6 बजे तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा, एमएसएमई से अधिशेष सौर ऊर्जा की खरीद मूल्य को 1.75 / यूनिट से बढ़ाकर 2.25 / यूनिट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा पर स्विच करने वाले मौजूदा उद्योग को सावधि ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी

3.7 इनके अलावा, उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन, जेडईडी प्रमाणीकरण सहित गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करना, पेटेंट फाइलिंग, सेवा लाइन और बिजली कनेक्शन शुल्क, किराया सहायता आदि के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

4. दीर्घकाल के लिए सरकारी भूमि पट्टे पर दी जाएगी:

राज्य में एक संतुलित क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार उद्योगों को 50 साल तक (प्रचलित नीति के अनुसार आगे बढ़ाने योग्य) के लिए बाजार के दर से 6% पर दीर्घकालिक पट्टे पर "सरकारी भूमि" प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। उद्योग भूमि को गिरवी रख सकेंगे।

5. संतुलित क्षेत्रीय विकास:

राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी एमएसएमई के साथ-साथ बड़े उद्योगों को संबंधित तालुकों में औद्योगिक विकास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। औद्योगिक रूप से कम विकसित तालुकों में परिचालन स्थापित करने वाले उद्योगों को वृद्धिशील लाभ दिया जाएगा।

6. स्टार्टअप की सहायता:

6.1 बीज सहायता को 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है।

6.2 प्रति स्टार्ट अप भरण-पोषण भत्ते को एक वर्ष के लिए 10,000 प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है और यदि कम से कम 1 महिला सह-संस्थापक हो तो उस स्टार्ट अप के लिए इस भत्ते को एक वर्ष के लिए प्रति माह 25,000 कर दिया गया है।

6.3 इसके अतिरिक्त, मिड-लेवल प्री-सीरीज स्टार्ट अप के लिए, गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड (जीवीएफएल) के तहत एक अलग फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा, स्टार्ट अप को अतिरिक्त 1% ब्याज सब्सिडी (यानी टर्म लोन पर 9% तक) मिलेगा।

6.4 समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले स्टार्ट अप को 10 लाख तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।

- 6.5 राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त त्वरण कार्यक्रमों में नामांकन के लिए 3 लाख प्रति स्टार्ट अप तक अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 6.6 सॉफ्ट स्किल सहायता: प्रतिपूर्ति के आधार पर "प्रबंधकीय प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल्स, मार्केटिंग कौशल, धन उगाहने, वित्त" पर प्रशिक्षण के लिए प्रति स्टार्ट अप 1 लाख तक की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- 6.7 मान्यता प्राप्त नोडल संस्थानों को शिक्षण सहायता के लिए प्रति स्टार्ट अप ₹ 1 लाख दिए जाएंगे (अधिकतम 15 लाख प्रति वर्ष प्रति संस्थान)

7. पुनर्वास भत्ते:

कोविड - 19 के कारण कई उद्योग अपने परिचालन को स्थानांतरित करने और / या आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की योजना बना रहे हैं। गुजरात ऐसी कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन देगा जो दूसरे देशों से स्थानांतरण की योजना बना रही हैं।

8. अनुसंधान एवं नवाचार

- 8.1 अनुसंधान और नवाचार एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, हमने सचेत रूप से नए आर एंड डी संस्थानों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। यह नीति आर एंड डी और उत्पाद विकास केंद्र स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों / संस्थानों को 5 करोड़ तक की सहायता प्रदान करेगी
- 8.2 किसी भी औद्योगिक उद्यम / औद्योगिक संघ से मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान / एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी कॉलेज से अनुबंध / प्रायोजित अनुसंधान कार्य के लिए सहायता, परियोजना की लागत का 50% माना जाएगा जिसमें भूमि और भवन की लागत शामिल नहीं है और इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख है।

9. औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास:

- 9.1 यह नीति निजी डेवलपर्स को राज्य में निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए निश्चित पूंजी निवेश का 25% और अधिकतम 30 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। वनबंधु तालुका के मामले में, यह नीति औद्योगिक पार्कों की स्थापना में निश्चित पूंजी निवेश का 50% और अधिकतम 30 करोड़ तक की सहायता करेगी। यह औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और अंतिम-मील

- कनेक्टिविटी के विकास में सहायक होगा। स्टॉप इयूटी प्रतिपूर्ति डेवलपर्स (स्टॉप इयूटी का 100%) और व्यक्तिगत इकाइयों (स्टैंप इयूटी का 50%) को दी जाएगी।
- 9.2 क्लस्टरों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे की स्थापना जैसे सड़क, भण्डारण सुविधा, फायर स्टेशन, भूमिगत उपयोगिताओं, आदि का निर्माण और उन्नयन के लिए योजना राशि का 80% या 25 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 9.3 यह नीति औद्योगिक क्लस्टर में मजदूरों को बेहतर आवास प्रदान करने के लिए विनिर्माण समूहों में डॉरमेटरी आवास के लिए वित्तीय सहायता का 80% या 25 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

10. सतत विनिर्माण:

- 10.1 जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट्स के लिए 75 लाख तक: पूंजीगत सब्सिडी का 50% या 75 लाख तक की राशि जीपीसीबी द्वारा प्रमाणित शून्य लिक्विड डिस्चार्ज के माध्यम से कम से कम 50% कचरा रिकवरी करने वाले उद्योगों को दी जाएगी।
- 10.2 स्वच्छ उत्पादन उपायों के लिए सहायता: इस नीति के तहत स्वच्छ उत्पादन तकनीक के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा प्रक्रिया जैसे कि कच्चे माल का प्रतिस्थापन और अनुकूलन, पानी, ऊर्जा की खपत अपशिष्ट उत्पादन में कमी के लिए एमएसएमई को संयंत्र और मशीनरी की लागत का 35% और बड़ी इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी की लागत का 10% (अधिकतम: 35 लाख) की सहायता दी जाएगी।

11. सामान्य पर्यावरण अवसंरचना:

- 11.1 सामान्य पर्यावरण अवसंरचना सुविधाओं के लिए सहायता परियोजना लागत की मौजूदा 25% से बढ़कर 40% या 50 करोड़ तक कर दी गई है
- 11.2 हरित क्षेत्रों का विकास: मौजूदा प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की हरित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापना / पुनर्वास / पुनर्निर्धारण के लिए परियोजना लागत का 25% या 25 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी।
- 11.3 एसपीवी द्वारा कम से कम 10 एमएसएमई में गठित कॉमन बॉयलर प्रोजेक्ट को निश्चित स्थापना लागत का 50% या 2 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

12. कौशल एवं प्रशिक्षण सहायता:

राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों और उपलब्ध श्रमिकों की कौशल आवश्यकता का अंतर विश्लेषण किया जाएगा। यह प्रासंगिक कौशल में स्थानीय आबादी को प्रशिक्षित करने के लिए एक रोडमैप बनाने में मदद करेगा और इस अंतर को पाट देगा।

राज्य कौशल विकास के महत्वपूर्ण संस्थानों, विशेष कौशल विकास केंद्रों, कौशल उन्नयन केंद्रों आदि की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी देगी।

इसके अलावा, इस नीति के तहत कौशल वृद्धि के लिए प्रति प्रशिक्षण प्रति व्यक्ति को 15000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

13. राज्य के अंदर और बाहर माल की आसान आवाजाही सुनिश्चित करने और निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समर्पित संगठन "गरुड़" का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण के तहत बनाया गया बुनियादी ढांचा उद्योगों को उत्पादन लागत कम करने में सहायता करेगा जिससे अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी।

14. समर्पित "संबंध प्रबंधकों" को औद्योगिक विस्तार ब्यूरो (iNDEXTb) द्वारा निवेशकों के लिए सरकार से संबंधित सभी प्रश्नों और अनुमोदन के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में नामित किया जाएगा।

15. निवेशक सुविधा पोर्टल (आईएफपी) - मेगा ऑनलाइन अनुमति: राज्य एकल खिड़की से लगभग 5 लाख आवेदन संसाधित किए गए हैं: निवेशक सुविधा पोर्टल (आईएफपी)। राज्य में व्यापार करने के लिए उचित वातावरण को और बेहतर बनाने के लिए, "मेगा परमिशन" की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके लिए निवेशक को 26 अलग-अलग राज्य से संबंधित स्वीकृतियों और शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए केवल एक आवेदन पत्र जमा करना होगा।

16. केंद्रीयकृत निरीक्षण प्रणाली: राज्य ने केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि पारदर्शिता लाने और व्यापार करने में आसानी हो सके।

17. पाइपलाइन उद्यम: नई परियोजनाएं जो पहले से ही पिछली नीति (गुजरात औद्योगिक नीति 2015) के तहत कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, उनमें कोई

बदलाव नहीं होगा। ऐसी निर्माण परियोजनाओं को नई गुजरात औद्योगिक नीति 2020 की रिलीज की तारीख से 1 वर्ष के भीतर और आम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 2 साल के भीतर चालू करने की आवश्यकता होगी।